भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4346
13.12.2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र

4346. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) एनसीएससीएम में स्थापित ऐसे अनुसंधन प्रभागों की संख्या कितनी है जो संरक्षण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सामुदायिक संवाद पर अत्याधुनिक अनुसंधान के साथ भू-स्थानिक विज्ञान को जोड़ती हैं;

(घ) क्या एनसीएससीएम वैज्ञानिक रूप से जलवायु परिवर्तन और तटीय पारिस्थितिकी, जीवन और आजीविका के लिए खतरे के कारण तटीय पर्यावरण की संचयी सुभेद्यता का नक्शा बनाने का प्रयास करेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त केन्द्र को विश्वस्तरीय संस्था के रूप में विकसित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) मंत्रालय ने तटीय संसाधनों और पर्यावरण तटीय क्षेत्र प्रबंधन सहित क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान करने हेतु राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई की स्थापना की है।

केंद्र के लक्ष्य और उद्देश्य हैं :

(i) तटीय क्षेत्रों, पर्यावरण, संसाधनों और प्रक्रियाओं से संबंधित विश्वस्तरीय ज्ञान संस्थान होने का प्रयास करना।

(ii) भारत में पारंपरिक तटीय और द्वीप समूह समुदायों के हित और कल्याण के लिए तटीय और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना, और

(iii) एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) से संबंधित नीति ओर वैज्ञानिक मामलों पर संघ और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित हितधारकों को सलाह देना।

(ग) एनसीएससीएम के छः (06) अनुसंधान प्रभाग हैं : भू-स्थानिक विज्ञान, सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), एकीकृत सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, तटीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, तटीय और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, ज्ञान, शासन और नीति, और अत्याधुनिक अनुसंधान और एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन इकाई।

(घ) और (ड.) भारतीय सर्वेक्षण और एनसीएससीएम ने पूरे भारतीय तट के लिए जोखिम रेखा को मानचित्रित किया है, जिसमें बाढ़, अपरदन और समुद्र स्तर वृद्धि के संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण शामिल है। इसके परिणाम संबंधित क्षेत्र में तटीय असुरक्षा के प्रबंधन में तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने हेतु सहायक उपाय हैं।

(च) भारत सरकार एनसीएससीएम को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में और उसे विश्वस्तरीय संस्थान बनने के प्रयासों में सहायता देने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीएससीएम विकसित अनुसंधान, नेटवर्किंग, वैज्ञानिक समितियों और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में समकक्ष समीक्षित प्रकाशन के माध्यम से अग्रणी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और एजेंसियों के साथ भागीदारी कर रही है। एनसीएससीएम के लिए, तटीय समुदायों और हितधारकों के लाभ के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण द्वारा तटीय प्रबंधन से संबंधित ज्ञान को प्रसारित करना अनिवार्य है। एनसीएससीएम की एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) योजना को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया गया है जिसे विश्व के अन्य भागों में भी दोहराया जा सकता है। केंद्र द्वारा तैयार तटीय प्रबंधन संबंधी विज्ञान आधारित ज्ञान का उपयोग बड़े पैमाने पर नीतिगत निर्णयों के लिए किया जा सकता है। पहली बार, तटीय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए एनसीएससीएम द्वारा एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन योजना जिसमें समग्र द्वीप समूह विकास योजनाएं शामिल हैं, को तैयार किया गया है। एनसीएससीएम, की नवीनतम अनुसंधान अवसंरचना विश्वस्तरीय अनुसंधान परिणामों को प्रस्तुत करती है और निर्णय समर्थन प्रणाली सीधे निर्णय लेने में समर्थ बनाती है। एनसीएससीएम की अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधा एकीकृत तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में एनसीएससीएम के साथ सहयोगपूर्ण अनुसंधान के लिए अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी एजेंसियों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराती है।

*****